Regd. No. PB/0176/2003-2005

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 29, 2005 (SRAVANA 7, 1927 SAKA)

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 29 जुलाई, 2005

संख्या 22/52/2005-5 विद्युत.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के फलोत्पादक उपयोग तथा इसके संरक्षण के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

1. **सौर जल तापीय प्रणाली का आज्ञापक उपयोग**

1. सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग भवनों के निम्नलिखित प्रवर्गों में आज्ञापक होगा, अर्थात् :—

(क) उद्योगों में जहां प्रसंस्करण के लिये गर्म पानी अपेक्षित है।

(ख) हस्पताल और नर्सिंग होम जिसमें सरकारी हस्पताल भी शामिल हैं।

(ग) होटल, मोटल और समारोह हाल।

(घ) जेल बैरकें और कैन्टीनें।

(ङ) समूह आवास समितियों/हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्थापित हाउसिंग काम्पलैक्स।

(च) नगरपालिका समितियों/निगमों तथा हुडा के सैक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी आवासीय भवन।

(छ) सभी सरकारी भवनों, आवासीय विद्यालयों, शैक्षणिक महाविद्यालयों, होस्टलों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन काम्पलैक्सों तथा विश्वविद्यालय इत्यादि।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) विशिष्टियों के अनुसार श्रेष्ठ रूप से डिज़ाईन किये गये उत्तम गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये राज्य में सौर जल तापीय प्रणालियों की आपूर्ति तथा स्थापना के लिये अनुमोदित स्त्रोत के रूप में कार्य करेगा।

3. सभी सम्बन्धित विभाग जैसे नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग, आवास बोर्ड, जन-स्वास्थ्य विभाग और वास्तुकला विभाग आदेश जारी होने की तिथि से दो मास के भीतर सौर जल तापीय प्रणालियों का उपयोग करने के लिये अपने नियम/उप-विधियां को संशोधित करेंगे।

Director,
Renewable Energy Deptt.

4. ये विभाग राज्य सरकार के निर्णय को मोनिटर करने तथा लागू करने की प्रगति अक्षय ऊर्जा विभाग को निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक आधार पर भेजने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर भी नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे।

2. सरकारी भवनों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों/बोर्डों/निगमों में काम्पैक्ट फलोरोसैंट लैम्प (सी०एफ०एल०) का आज्ञापक उपयोग

1. सरकारी सैक्टर/सरकारी सहायता प्राप्त सैक्टर/बोर्ड तथा निगमों/स्वायत निकायों में सभी नये निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में इन्केंडेसैंट बल्बों के प्रयोग पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध किया जाता है।

2. यह आज्ञापक होगा कि विद्यमान भवनों में खराब इन्केंडेसैंट बल्बों को जब बदला जाये तो केवल काम्पैक्ट फलोरोसैंट लैम्प (सी०एफ०एल०) से ही बदला जायेगा।

3. विद्युत उपयोगिता में, नये कनैक्शन अथवा नया लोड जारी/स्वीकृत करते समय पारम्परिक बल्ब के स्थान पर सी.एफ.एल. के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक उपांतरण करना होगा।

3. कृषि क्षेत्र में आई०एस०आई० मार्कड मोटर पम्प सैट, पावर कैपिसीटर, फुट/रिफलैक्स वाल्व का आज्ञापक उपयोग

1. सभी नये ट्यूबवैल कनैक्शनों के लिये आई०एस०आई० मार्कड पम्प सैट्स तथा एसैसरीज़ का उपयोग आज्ञापक होगा।

2. राज्य में केवल आई०एस०आई० मार्कड पम्प सैट्स का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये इस आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ट्यूबवैल कनैक्शनों के लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक संशोधन करेगा।

4. ऊर्जा कुशल भवन डिज़ाईन को बढ़ावा देना

1. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले सभी नये भवनों में 30 जून, 2006 से ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिज़ाईन धारणा जिसमें अक्षय ऊर्जा तकनीक भी शामिल है, सम्मिलित करेंगे।

2. वास्तुकला विभाग भविष्य में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले सभी भवनों में ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाईन धारणा को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा। वास्तुकला विभाग में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र निर्मित किये जाने वाले सभी नये भवनों की योजना/मानचित्रों की जांच करने तथा सुनिश्चित करने के लिये कि ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिज़ाईन धारणा की सभी विशेषताओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया के लिये एक समिति गठित की जायेगी।

3. वास्तुकला विभाग इन उपायों के समन्वय तथा मोनिटरिंग के लिये एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा जो निदेशक, अक्षय ऊर्जा विभाग को इस बारे में प्रगति की सूचना देगा।

इस मामले में पूर्व में जारी किये गये सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

एस० सी० चौधरी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 29th July, 2005

No. 22/52/05-5P.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana, namely :—

1. **Mandatory use of Solar Water Heating Systems**

1. The use of solar water heating systems will be mandatory in the following categories of buildings, namely :—

(i) Industries where hot water is required for processing.

(ii) Hospitals and Nursing homes including Government Hospitals.

(iii) Hotels, Motels and Banquet halls.

(iv) Jail Barracks, Canteens.

(v) Housing Complexes set up by Group Housing Societies/Housing Boards.

(vi) All residential buildings built on a plot of size 500 square yards and above falling within the limits of municipal committees/corporations and Haryana Urban Development Authority sectors.

(vii) All Government buildings, Residential Schools, Educational Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, District Institutes of Education and Training, Tourism Complexes and Universities etc.

2. Haryana Renewable Energy Development Agency will act as an approved source for supply and installation of solar water heating systems in the State to ensure the installation of optimally designed quality systems as per the specifications.

3. All the line departments like Town and Country Planning Department, Urban Development Department, Public Works Department (Building and Roads), Housing Board, Public Health Department and Architecture Department will amend their rules/bye-laws within a period of two months from the date of issue of this order to make the use of solar water heating systems mandatory.

4. These departments will also designate a district and a state level nodal officer to monitor and report the progress of enforcement of the State Government decisions to the Department of Renewable Energy, Haryana on Quarterly basis in the prescribed format.

2. Mandatory use of Compact Fluorescent Lamp (CFL) in Government Buildings/Government Aided Institutions/Boards/Corporations

1. The use of incandescent lamps in all new buildings/institutions constructed in Government sector/Government Aided sector/Board and Corporation/Autonomous bodies is banned with immediate effect.

2. It will be mandatory that in existing buildings the defective incandescent lamps when replaced, would be replaced by only compact fluorescent lamps (CFL).

3. Power utilities will affect necessary modification in the load demand notices within two months time from the date of issue of this order to promote the use of Compact Fluorescent Lamps instead of conventional bulbs while releasing/sanctioning new connections/loads.

3. Mandatory use of ISI marked Motor pump sets, Power capacitor, Foot/Reflex valves in Agriculture Sector

1. For all new tubewell connections, the use of ISI marked pump sets and accessories will be mandatory.

2. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam/Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam will make the amendments in the load demand notices for tubewell connections within two months time from the date of issue of this order to ensure use of only ISI marked pumps in the State.

4. Promotion of Energy Efficient Building Design

1. All the new buildings to be constructed in the Government/Government Aided sector will incorporate energy efficient building design concepts including Renewable Energy Technologies with effect from 30th June, 2006.

2. The Architecture Department will ensure the incorporation of energy efficient building design concepts in all buildings to be constructed in future in the Government/Government Aided sector. A committee shall be formed in the Architecture Department to examine all new building plans/drawings to be constructed in the Government/Government Aided sector to ensure that all the features of the energy efficient building design concepts, have been incorporated in these.

3. The Architecture Department will designate a nodal officer for coordination and monitoring of these measures who will report the progress in this regard to the Director, Renewable Energy Department, Haryana.

The above orders supersede all previous orders in this matter and come into force with immediate effect.

S.C. CHAUDHARY,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Renewable Energy Department.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 7th September, 2006]

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 7th September, 2006

No. 22/52/05-5P.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No. 22/52/05-5P, dated the 29th July 2005, namely :—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No. 22/52/05-5P, dated the 29th July, 2005 after para 2, the following para shall be inserted namely :—

"2A. Mandatory use of T-5 28 watt Energy Efficient Tube light System/Retrofit Assembly in Government Buildings/Government Aided Institutions/Boards/Corporations

1. The use of 40 watt conventional tube lights with blast in all new buildings/institutions constructed in Government sector/Government aided sector/ /Boards and Corporations/Autonomous Bodies is banned with immediate effect. These buildings/institutions constructed in Government sector/ Government aided sector/Boards and Corporations/Autonomous Bodies shall use only T-5 28 watt energy efficient tube light system.

2. It shall be mandatory that in existing buildings, the defective 40 watt conventional tube lights with blast, when replaced, would be replaced by only 28 watt retrofit assembly.

3. Power utilities shall affect necessary modification in the load demand notices within two months time from the date of issue of this order to promote the use of T-5 28 watt energy efficient tube light system/retrofit assembly instead of 40 watt conventional tube light with blast while releasing/sanctioning new connections/loads".

S.C. CHAUDHARY,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Renewable Energy Department.